

विजयवर्मा भारस्कर भोयाव

23 OCT 2010

# खजुराहो निवेश सम्मेलन काफी सफल

पहले दिन एक लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू

बिजनेस भारस्कर • खजुराहो

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खजुराहो में आयोजित निवेश सम्मेलन काफी सफल साबित हो रहा है। इस वैश्विक सम्मेलन के पहले ही दिन राज्य सरकार ने 14 कंपनियों के साथ एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सम्मेलन के दूसरे दिन भी इतने ही एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सम्मेलन के पहले दिन राज्य सरकार ने 14 कंपनियों के साथ 1,20,637 करोड़ रुपये के 22 एमओयू किए हैं। दूसरे दिन भी इतने ही एमओयू होने का अनुमान है। पहले दिन सबसे बड़ा समझौता दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) और ट्राइफेक के बीच हुआ। इसका आकार 33,147 करोड़ रुपये है। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक ने 6,000 करोड़ रुपये के तीन एमओयू किए हैं। कंपनी की



सम्मेलन को संबोधित करते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

तीन नए सीमेंट प्लांट लगाने की योजना है। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने सीमेंट और फूड प्रोसेसिंग के लिए 1,850 करोड़ रुपये के पांच एमओयू किए हैं।

इनके अलावा आज एस्सार स्टील ने 2,450 करोड़, गेल इंडिया लिमिटेड ने 4,900 करोड़, जियो मैसूर सर्विसेस ने सोना खनन के लिए 300 करोड़, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने 18,500 करोड़, एनटीपीसी ने 20,000 करोड़,

जीएमआर बुंदेलखंड ने बिजली के लिए 14,000 करोड़, एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 2,970 करोड़, रियो टिटो ने खनन के लिए 2,300 करोड़ रुपये और के.आर.एनर्जी ने 14,000 करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं।

विजयवर्गीय ने कहा कि सभी एमओयू काफी जांच-परख के बाद किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार का विश्वास है कि ये अमल में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि

## कितने का समझौता

कंपनी	एमओयू का आकार
डीएमआईसी-ट्राइफेक	33,147
एनटीपीसी	20,000
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज	18,500
जीएमआर बुंदेलखंड	14,000
के.आर. एनर्जी	14,000
अल्ट्राटेक	6,000
गेल इंडिया	4,900
एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स	2,970
एस्सार स्टील	2,450
रियो टिटो	2,300
जयप्रकाश एसोसिएट्स	1,850
जियो मैसूर	300

(राशि करोड़ रुपये में)

पिछले छह महीने से सरकार इस पर काम कर रही थी। जिन कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिये थे उनके बारे में काफी पड़ताल के बाद ही उनसे समझौते को मंजूरी दी गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन समझौतों पर जल्द काम शुरू हो जाएगा और सरकार लगातार इनकी निगरानी करेगी। यदि कोई इसे लेकर गंभीर नहीं होगा तो उसका एमओयू निरस्त कर दिया जाएगा।